

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज करेंगे जिला चिकित्सालय के नए 300 बिस्तरीय भवन का लोकार्पण



इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जिला चिकित्सालय के नवनिर्मित 300 बिस्तरीय भवन का लोकार्पण करेंगे। लगभग 83 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह चार मंजिला आधुनिक भवन जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करेगा। नवीन भवन के शुरू होने से मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा अस्पताल की उपचार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित इस

भवन में विभिन्न विभागों के लिए पर्याप्त स्थान, मरीजों के लिए बेहतर वार्ड तथा आवश्यक स्वास्थ्य अधोसंरचना विकसित की गई है।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी। जिला चिकित्सालय के इस नए भवन के लोकार्पण से इंदौर सहित आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।

व्यापार समझौता लागू व्हिस्की, टेक्सटाइल, ऑटो और सेवा क्षेत्र को मिलेगा बड़ा लाभ, द्विपक्षीय व्यापार में आएगी नई तेजी

भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीडीटीए) 15 जुलाई 2026 से लागू हो गया है। लगभग एक वर्ष पहले हस्ताक्षरित इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई गति देना है।

नई दिल्ली। अनुमान है कि इससे आने वाले वर्षों में भारत-ब्रिटेन का द्विपक्षीय व्यापार 25 अरब पाउंड से अधिक बढ़ सकता है। समझौते के तहत कई उत्पादों पर आयात शुल्क में चरणबद्ध कमी या समाप्ति का प्रावधान किया गया है। भारत के टेक्सटाइल, परिधान, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण,



इंजीनियरिंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और औषधि उद्योग को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। वहीं भारत में ब्रिटिश व्हिस्की, ऑटोमोबाइल और कुछ अन्य उत्पादों पर शुल्क में चरणबद्ध राहत दी जाएगी।

इस समझौते से सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं और पेशेवर सेवाओं के क्षेत्र में भी नए अवसर खुलने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना

है कि इससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी, विदेशी निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का कहना है कि यह समझौता भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे तथा उद्योग, निवेश और रोजगार को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

जनसुनवाई बनी विश्वास का केंद्र, हर जरूरतमंद तक पहुंची रही प्रशासन की संवेदनशील पहल

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने संवेदनशीलता से सुनी समस्याएं, मौके पर दिए समाधान के निर्देश

राजेश धाकड़

इंदौर कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार आयोजित हो रही साप्ताहिक जनसुनवाई आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का सशक्त माध्यम बना रही है।

जनसुनवाई में पहुंचे विभिन्न आवेदकों की समस्याओं को कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए त्वरित सहायता सुनिश्चित की। जनसुनवाई में एक भावुक पल उस समय देखने को मिला, जब श्रीमती भावले अपनी तीन नातियों सुश्री सिद्धि भावले, तमन्ना भावले एवं हिमांशी भावले के साथ अपनी समस्या लेकर पहुंचीं। उन्होंने कलेक्टर श्री शिवम वर्मा को बताया कि बच्चियों के माता-पिता का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके बाद उनके पालन-पोषण की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे बच्चियों की स्कूल फीस जमा नहीं हो पा रही हैं। कलेक्टर श्री



शिवम वर्मा ने उनकी बात गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को बच्चियों की स्कूल फीस माफ कराने के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने एवं शासन की पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी निर्देशित किया। प्रशासन की इस संवेदनशील पहल से बच्चियों और उनकी नानी के चेहरे पर मुस्कान लौट

आई तथा उन्होंने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसी प्रकार दिव्यांग बालक मिहिर चौहान अपने पिता श्री लखन चौहान के साथ जनसुनवाई में पहुंचे। श्री लखन चौहान ने बताया कि उनके पुत्र को सुनने में परेशानी होती है और उसके कान में श्रवण यंत्र लगा हुआ है। श्रवण यंत्र की बैटरी समाप्त हो जाने के कारण उसे

काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण नई बैटरी खरीदने में असमर्थ है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने बालक की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल 18 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही बालक के उपचार एवं आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया। एक अन्य प्रकरण में श्रीमती राखी दुबे अपनी समस्या लेकर जनसुनवाई में पहुंचीं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में उन्हें वात्सल्य योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन पिछले एक वर्ष से उनके बच्चों के खाते में योजना की राशि जमा नहीं हो रही है, जिससे परिवार आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बेटी कक्षा 11वीं में अध्ययनरत है, जबकि छोटा बेटा ऑटिज्म से पीड़ित है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने प्रकरण को गंभीरता से सुनते हुए तत्काल 24 हजार

रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में अधिकारियों ने आमजन से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशन में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कई आवेदन प्राप्त हुए जिसमें मुख्य रूप से प्लॉट, संपत्ति, पारिवारिक विवाद, चिकित्सा सहायता और रोजगार से जुड़े प्रकरण रहे। जनसुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर श्री नवजीवन विजय पवार, श्री रोशन राय, श्री रिकेश वैश्य सहित सभी विभागीय अधिकारियों में नागरिकों की समस्याओं को सहानुभूति के साथ सुना और उनका निराकरण किया।

करैरा तहसील में प्रशासनिक अव्यवस्था का आरोप
कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की गैरमौजूदगी में BNSS धारा 170 के आरोपियों को भेजा गया जेल, वीडियो आया सामने



हेमंत भार्गव

MP शिवपुरी | करैरा तहसील एक बार फिर प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर विवादों में आ गई है। रविवार को BNSS की धारा 170 के मामलों में गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के लिए तहसील लाया गया, लेकिन आरोप है कि उस समय तहसील परिसर में कोई भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अपनी सीट पर मौजूद नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अधिवक्ता अनिल कुमार दुबे ने पुलिस और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जानकारी के अनुसार, थाना अमोला पुलिस एक आरोपी तथा थाना करैरा पुलिस दो आरोपियों को लेकर तहसील पहुंची थी। अमोला थाना के आरोपी कोमल आदिवासी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार दुबे भी तहसील पहुंचे। उनका आरोप है कि वहां केवल एक बाबू मौजूद था, जिसने जेल वारंट तैयार करते हुए कथित रूप से कहा कि तहसीलदार शैलेंद्र भार्गव की जेलर से बात हो चुकी है और वे अगले दिन वारंट पर हस्ताक्षर कर देंगे। अधिवक्ता ने इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए इसे नियमों के विपरीत बताया। अधिवक्ता के विरोध के बाद अमोला थाना से लाए गए आरोपी को छोड़ दिया गया, जबकि करैरा थाना से लाए गए दो आरोपियों को कथित तौर पर तहसीलदार के हस्ताक्षर के बिना ही जेल भेज दिया गया। अधिवक्ता का दावा है कि उन्होंने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया है, जिसमें तहसील कार्यालय की स्थिति, तहसीलदार से फोन पर हुई बातचीत तथा जेल में आरोपियों को दाखिल किए जाने, पुलिस कर्मियों द्वारा जेल वारंट पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर नहीं दिखाने से जुड़े दृश्य मौजूद हैं। अधिवक्ता अनिल दुबे ने अमोला थाना पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि मामला दो पक्षों के बीच भूमि विवाद से जुड़ा था, लेकिन पुलिस ने दूसरे पक्ष को बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी। उनके अनुसार, यदि विवाद भूमि से संबंधित था तो नियमानुसार SDM के समक्ष आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। दो दिन पहले भी खाली मिला था तहसील कार्यालय, अब फिर दोहराई

गई अव्यवस्था; करैरा तहसील की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल- अधिवक्ताओं और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है। उनका आरोप है कि दो दिन पूर्व भी करैरा तहसील कार्यालय में तहसीलदार, रीडर और अन्य कर्मचारी अनुपस्थित मिले थे, जिससे आम लोगों को घंटों परेशान होना पड़ा। अब रविवार की घटना ने एक बार फिर तहसील की प्रशासनिक व्यवस्था और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रशासन का पक्ष- नायाब तहसीलदार करैरा, शैलेंद्र भार्गव का कहना है-कि बिना वारंट पर हम अपने हस्ताक्षर के क्यों भेजेंगे, जेल में भी कोई बिना हस्ताक्षर वाला वारंट नहीं लेगा, आप जेल में भी पूछ सकते हो सारे आरोप निराधार है

विनोद छावई थाना प्रभारी करैरा का कहना है-कि जेल वारंट में हैं हस्ताक्षर आज का ही मामला था, जिसमें छत्रपाल एवं अनिल के खिलाफ 170 लगाई थी। जो जेल वारंट बनाया है, उसमें तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं। पक्षकार के वकील को भी हम वो कागज नहीं दिखा सकते। मामले को लेकर अधिवक्ता रितुराज यादव ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि प्रशासन का दावा है कि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार तहसील परिसर में उपस्थित थे, तो इसकी सत्यता तहसील परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से आसानी से स्पष्ट की जा सकती है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की।

वहीं अधिवक्ता प्रशांत त्रिपाठी ने कहा कि करैरा तहसील में लगातार सामने आ रही प्रशासनिक अनियमितताओं और अधिकारियों की निरंकुशता को देखते हुए, अधिवक्ता समुदाय इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेने पर विचार कर रहा है। क्षेत्र के लोगों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करी है ताकि सत्य सबके समक्ष आ सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर विराम लगाया जा सके। अब लोगों की नजरें जिला प्रशासन पर टिकी हैं, देखना होगा प्रशासन इस घटना को लेकर क्या कार्रवाई करता है।

11 दिवसीय श्री हरि दर्शन पदयात्रा महोत्सव

सवारिया मित्र मंडल पदयात्रा संघ ने पकड़ी रफ्तार

खुशबू श्रीवास्तव

इंदौर। श्री सांवरिया मित्र मंडल पदयात्री संघ, इंदौर द्वारा आगामी 11 दिवसीय श्री हरि दर्शन पदयात्रा महोत्सव की तैयारियों को लेकर सोमवार को राजश्री होटल, एमओजी लाइन, पावर हाउस के पास, गंगवाल बस स्टैंड पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभात फेरी को भव्य, अनुशासित एवं धर्ममय स्वरूप देने सहित पदयात्रा महोत्सव की विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने प्रभात फेरी के सफल आयोजन के लिए अपने सुझाव एवं विचार रखे।

सभी ने एकजुट होकर इस वर्ष की प्रभात फेरी एवं पदयात्रा महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। आयोजन समिति ने कहा कि प्रभात फेरी केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज में भक्ति, संस्कार, अनुशासन और एकता का संदेश देने का माध्यम



है। बैठक में प्रभात फेरी के मार्ग, स्वागत व्यवस्था, अनुशासन, प्रचार-प्रसार, सेवा कार्य, श्रद्धालुओं की सुविधाओं तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर जिम्मेदारियां भी तय की गईं। सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से पूर्ण समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से कमलेश जी शर्मा (लालू भैया), धनराज कुमावत, मोहित गुप्ता,

राधेश्याम जी मंडोवरा, बालू जी टाक, हरिसिंह ठाकुर, नरेश जी खुखवाल एवं ओंकार जी लोयसा सहित बड़ी संख्या में मंडल के पदाधिकारी, सदस्य एवं प्रभात फेरी कर्ता उपस्थित रहे। अंत में सभी ने श्रद्धा और उत्साह के साथ आगामी आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लेते हुए अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को प्रभात फेरी एवं पदयात्रा महोत्सव से जोड़ने का आह्वान किया।

करैरा तहसील में फिर प्रशासनिक अव्यवस्था! दोपहर 2 बजे तक खाली रहे न्यायालय

हेमंत भार्गव

करैरा (शिवपुरी)। करैरा तहसील कार्यालय में सोमवार को एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था सवाल के घेरे में आ गई। आरोप है कि दोपहर करीब 2 बजे तक एसडीएम सहित राजस्व न्यायालयों में कोई भी सक्षम अधिकारी अपनी सीट पर मौजूद नहीं था। अधिकारियों की अनुपस्थिति से किसान, आम नागरिक और अधिवक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे तहसील की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार करैरा तहसील परिसर में एसडीएम न्यायालय, एक फील्ड तहसीलदार न्यायालय तथा तीन राजस्व कार्यपालिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संचालित हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन न्यायालयों में अधिकारियों की अनुपस्थिति अब आम बात बनती जा रही है, जिसके कारण नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अन्य राजस्व मामलों की सुनवाई समय पर नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि वे कई दिनों से अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी उपलब्ध नहीं होने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। इससे उनका समय और आर्थिक संसाधन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। वहीं, अधिवक्ताओं ने भी अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर कड़ी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि सोमवार को कई राजस्व प्रकरण सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थे, लेकिन संबंधित अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप पक्षकारों और अधिवक्ताओं को बिना सुनवाई के वापस लौटना पड़ा। गौरतलब है कि इससे पहले भी करैरा तहसील में अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति को लेकर शिकायतें सामने आ चुकी हैं। लगातार मिल रही ऐसी शिकायतों ने तहसील की प्रशासनिक व्यवस्था और आमजन को मिलने वाली राजस्व सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। किसानों और अधिवक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि सभी अधिकारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण कराया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

राज्य शासन ने जिले के चार मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को उपायुक्त (विकास) के पद पर किया पदोन्नत



नवल किशोर

कटनी। गत दिवस राज्य शासन ने कटनी जिले और जिला पंचायत कटनी में पदस्थ चार मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को उपायुक्त (विकास) पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सर्व श्री जनपद पंचायत कटनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप सिंह, रीठी के राजेश नरेंद्र सिंह, ढीमरखड़ा के यजुवेंद्र कोरी और बड़वारा की सुश्री प्रभा तेकाम को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थापन्न रूप से उपायुक्त (विकास) के पद पर पदोन्नति दी गई है।

सुश्री कौर ने दी बधाई- जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने चारों पदोन्नत अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सुनहरे उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि समस्त सीईओ अपने कार्य क्षेत्र में निष्ठा एवं परिश्रम के साथ जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर जन हितैषी योजनाओं का प्रभावी और परिणाम मूलक क्रियान्वयन सुनिश्चित करते रहें ताकि अंतिम छोर पर बैठे हुए पात्र व्यक्ति को पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ मिल सके। हम सब का यह संयुक्त प्रयास रहे कि राज्य शासन और जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन बखूबी नियत समय में होता रहे।

महापौर श्रीमती सूरि ने सुनीं आवेदकों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समयबद्ध निराकरण के निर्देश

नवल किशोर

कटनी। नगर पालिक निगम कटनी में 14 जुलाई मंगलवार को आयोजित महापौर जनसुनवाई में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरि के समक्ष प्रस्तुत कीं।

जनसुनवाई के दौरान पेयजल, सड़क, नाली, स्वच्छता, राजस्व, अतिक्रमण सहित विभिन्न नागरिक सुविधाओं से जुड़े प्रकरणों पर सुनवाई की गई। महापौर श्रीमती सूरि ने प्रत्येक आवेदन पर गंभीरतापूर्वक सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं समयबद्ध कार्रवाई



सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई नागरिकों की समस्याओं के प्रभावी एवं पारदर्शी समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है।

नागरिकों कि प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कर आवेदकों को समय पर राहत प्रदान की जाए तथा प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

सभी शाखाओं की उपस्थिति से शिकायतों के निराकरण में मिली सुविधा

जनसुनवाई के दौरान नगर निगम की विभिन्न शाखाओं के अधिकारी एक ही स्थान पर मौजूद रहे, जिससे नागरिकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

कई प्रकरणों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर कार्रवाई प्रारंभ

कराई गई, जबकि गंभीर मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए निर्देश दिए गए।

प्रत्येक मंगलवार जनसुनवाई का लाभ उठाने की अपील

महापौर श्रीमती सूरि ने शहरवासियों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक मंगलवार आयोजित होने वाली महापौर जनसुनवाई में उपस्थित होकर अपनी शिकायतें सीधे नगर निगम के समक्ष रखें। उन्होंने कहा कि नगर निगम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी एवं जवाबदेह सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

कटनी पुलिस के अधिकारियों ने सुनी आमजन की समस्याएं, त्वरित निराकरण के लिए निर्देश

कटनी। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण एवं प्रभावी समाधान हेतु प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई के क्रम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मोर्य, एसडीओपी स्लीमनाबाद श्रीमती आकांक्षा चतुर्वेदी, एसडीओपी वि.गढ़ धीरेन्द्र धार्वे, डीएसपी मुख्यालय रत्नेश मिश्रा ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को प्राथमिकता से लेते हुए संबंधित थाना प्रभारी एवं को त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कुछ प्रकरणों में साइबर संबंधी शिकायतों के प्राप्त होने पर, फरियादियों को शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने एवं साइबर अपराधों से जागरूक रहने



की हिदायत भी पुलिस अधिकारियों द्वारा फरियादियों को दी गई। एवं आवश्यक कार्यवाही के निर्देश सायबर सेल को दिये गये।

जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों में मुख्यतः पारिवारिक विवाद, आपसी विवाद, पैसों के लेन-देन से संबंधित मामले, पुलिस द्वारा सुनवाई न होने की शिकायतें, भूमि/प्लॉट संबंधी धोखाधड़ी, महिला अपराध एवं अन्य पुलिस से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। कुछ समस्याएं अन्य विभागों से संबंधित होने पर, आवेदकों को संबंधित विभाग में जाने की समझाइश भी दी गई।

उत्साह का माहौल, ब्रह्मकमल का खिलना अत्यंत शुभ

कोरबा। पाली नगर पंचायत पाली के दुर्गा पंडाल के समीप निवासी रमेश डिकसेना के घर सोमवार देर रात दुर्लभ ब्रह्मकमल का फूल खिलने से पूरे मोहल्ले में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बन गया। जैसे ही ब्रह्मकमल के खिलने की जानकारी परिवारजनों को मिली, सभी ने दीप प्रज्वलित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और आरती उतारी।

परिवार के सदस्यों ने इसे भगवान की विशेष कृपा और शुभ संकेत बताते हुए स्वयं को सौभाग्यशाली बताया। ब्रह्मकमल के खिलने की सूचना आसपास के क्षेत्र में फैलते ही बड़ी संख्या में लोग रमेश डिकसेना के घर पहुंचने लगे। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने श्रद्धापूर्वक ब्रह्मकमल के



दर्शन किए तथा भगवान से परिवार और नगर की सुख-समृद्धि एवं मंगल की कामना की। कई श्रद्धालुओं ने इस दुर्लभ दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद किया। देर रात तक दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार ब्रह्मकमल का



खिलना अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक माना जाता है। इसकी मनमोहक छटा और सुगंध ने सभी को आकर्षित किया। श्रद्धालुओं ने इसे ईश्वर की विशेष कृपा बताते हुए कहा कि ऐसे दुर्लभ और पवित्र दृश्य के दर्शन जीवन में विले ही होते हैं।

बागेश्वर धाम में जमीन विवाद पर गोलीकांड का आरोप: धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर गंभीर आरोप, पुलिस जांच में जुटी

छतरपुर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग पर गोली चलाने का गंभीर आरोप लगा है। यह घटना छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़ा में हुई, जहां गौशाला से लगी जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है।

घायल मोतीलाल कुशवाहा का आरोप है कि जमीन विवाद के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और उन पर गोली चलाई गई। गोली लगने के बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना की शिकायत राजनगर थाने में की गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित का आरोप है कि क्षेत्र में किसानों पर जमीन बेचने का दबाव

बनाया जा रहा था और इसी विवाद के बीच यह घटना हुई। हालांकि, इन आरोपों की अभी पुलिस द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। मामले में एफआईआर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। घटना के समय तक शालिग्राम गर्ग या बागेश्वर धाम की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यह मामला बागेश्वर धाम से जुड़े होने के कारण प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया है। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि घटना की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं और आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है।

Airtel ने पुरी रथ यात्रा 2026 से पहले ओडिशा में किया नेटवर्क का महा-विस्तार

नई दिल्ली। भारत की दिग्गज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों में से एक, भारती एयरटेल ने पुरी रथ यात्रा की तैयारी के तहत पूरे ओडिशा में अपने नेटवर्क के बड़े पैमाने पर विस्तार की घोषणा की।

सालाना रथ यात्रा के दौरान वॉइस और डेटा ट्रैफिक में होने वाली भारी बढ़ोतरी को देखते हुए, एयरटेल ने अपनी तैयारी के तहत पुरी में अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। इसमें पवित्र शहर तक जाने वाले सभी मुख्य सड़क और रेल रूट शामिल हैं। इन अपग्रेड्स में 5G सेवाओं को शुरू करना भी शामिल है। इनका मकसद नेटवर्क की बढ़ती मांग को अच्छे से संभालना और तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के दौरान बिना रुकावट वॉइस कनेक्टिविटी और हाई-स्पीड डेटा सेवाएं सुनिश्चित करना है। पिछले 12 महीनों में, कंपनी ने पूरे राज्य में 1,500 से ज्यादा नए 5G साइट्स लगाए हैं। इससे ओडिशा के 30 जिलों में इसका नेटवर्क कवरेज काफी मजबूत हुआ है।

अखंड ज्योति प्रज्वलित के साथ झूलेलाल चालीहां महोत्सव का शुभारंभ, 40 दिनों तक गूंजेंगे धार्मिक भजन

नवल किशोर

कटनी। सिंधी समाज के आराध्या देव झूलेलाल जी के भक्ति का महापर्व 'चालीहां महोत्सव' हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है। इस पावन अवसर पर अखंड ज्योति प्रज्वलित कर 40 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठानों का भव्य शुभारंभ किया गया।

40 दिनों तक होंगे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम

इस महोत्सव के दौरान आगामी 40 दिनों तक रोजाना विशेष पूजा-अर्चना, आरती और पल्लव (प्रार्थना) का आयोजन किया जाएगा।

समाज के श्रद्धालुओं द्वारा विश्व शांति और खुशहाली की कामना के



साथ यह कठिन व्रत रखा जा रहा है। इन 40 दिनों में विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है।



भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के नव रूप का दर्शन

पुरी। ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र 'नवयौवन दर्शन' (नेत्रोत्सव) होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिनों तक चलने वाले अनसर (एकांतवास) के दौरान सार्वजनिक दर्शन बंद रहते हैं।

इस अवधि के बाद

आज पहली बार श्रद्धालु भगवान के नवयौवन स्वरूप के दर्शन करेंगे।



धार्मिक मान्यता के अनुसार

स्नान पूर्णिमा पर 108 कलशों से महाभिषेक के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और एकांत में विश्राम करते हैं। इस दौरान विशेष आयुर्वेदिक उपचार, श्रृंगार और गुप्त अनुष्ठान संपन्न होते हैं। नवयौवन दर्शन के दिन भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है और नेत्रों का पुनः अंकन (नेत्रोत्सव) होने के बाद वे भक्तों को दर्शन देते हैं। नवयौवन दर्शन के बाद 16 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा भव्य रथों पर सवार होकर श्री गुंडिचा मंदिर की यात्रा करेंगे। इस अवसर पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पुरी पहुंचने की संभावना है।

पटवारी के भाई नाना पटवारी की बढ़ीं मुश्किलें

इंदौर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी से जुड़े मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियां मोबाइल फोन, डिजिटल गतिविधियों, बैंक लेनदेन और कथित ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े संभावित संपर्कों की पड़ताल कर रही हैं। हालांकि अभी तक किसी भी आरोप पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है और जांच जारी है। जांच से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने नाना पटवारी से कई घंटे पूछताछ की। उनका कथित तौर पर ड्रग्स पैडलरों से आमना-सामना भी कराया गया। पुलिस मोबाइल फोन की सर्व हिस्ट्री, डिजिटल डेटा और वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण कर रही है।

रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जांच के दौरान मोबाइल में ऑनलाइन



सट्टेबाजी से जुड़े ऐप और लिंक तथा कुछ संदिग्ध संपर्क नंबर मिलने के पहलुओं की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनका किसी संगठित नेटवर्क से संबंध है या नहीं। फिलहाल इन दावों की जांच जारी है और इन्हें अंतिम निष्कर्ष नहीं माना गया है। जांच का एक अन्य पहलू कथित वीआईपी पार्टियों और ड्रग्स नेटवर्क से संभावित संबंधों का है। पुलिस उन लोगों से

भी पूछताछ कर रही है जिनका नाम जांच के दौरान सामने आया है। साथ ही बैंक लेनदेन और डिजिटल साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है। दूसरी ओर, नाना पटवारी और जीतू पटवारी ने सार्वजनिक रूप से आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। नाना पटवारी ने यह भी कहा कि उन्होंने वर्षों पहले नशे की आदत छोड़ दी थी और वर्तमान आरोपों को स्वीकार नहीं किया।

पुलिस का कहना है

जांच अभी जारी है और डिजिटल फॉरेंसिक, मोबाइल डेटा, बैंक रिकॉर्ड तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी भी आरोप पर अंतिम निष्कर्ष या दोष सिद्ध नहीं हुआ है।

इंदौर से भोपाल तक साइकिल रैली शुरू

इंदौर। शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार, लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों और छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को इंदौर से भोपाल तक "छात्रों की गूंज" अभियान के तहत जन-जागरण साइकिल रैली की शुरुआत की। रीगल तिराहे से प्रारंभ हुई इस रैली में बड़ी संख्या में युवा, छात्र और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली का नेतृत्व मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कर रहे हैं, जबकि उनके साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी साइकिल चलाते हुए नजर आए। रैली के शुभारंभ के दौरान कांग्रेस नेताओं ने इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का अभियान बताया। इंदौर से शुरू हुई यह यात्रा विभिन्न शहरों और

कस्बों से गुजरते हुए भोपाल पहुंचेगी, जहां कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएगी। आयोजन को लेकर कांग्रेस संगठन ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई दिनों से तैयारियां की थीं, जिसका असर रैली में युवाओं की अच्छी भागीदारी के रूप में दिखाई दिया। साइकिल रैली में पूर्व मंत्री सचिन यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, एआईसीसी सचिव सत्यनारायण पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा शेख अलीम, अमन बजाज, पिंटू जोशी, सोनिला मिमरोट, रुबीना खान, दीपू यादव, संजय बाकलीवाल, अमित पटेल और राजेश चौकसे सहित कई स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ता भी रैली में शामिल हुए।

राम मंदिर ट्रस्ट की भूमि खरीद पर भी उठे सवाल



नजूल और देवोत्तर संपत्तियों की खरीद के आरोप, एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

नई दिल्ली। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े भूमि सौदों को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ट्रस्ट ने नजूल भूमि और मंदिरों की देवोत्तर संपत्तियों सहित विभिन्न प्रकार की जमीनों की खरीद में अनियमितताएं कीं। इन आरोपों के बीच अब सबकी नजर विशेष जांच दल (एसआईटी) की अंतिम रिपोर्ट पर है कि वह केवल चढ़ावा चोरी के आरोपों तक सीमित रहती है या भूमि सौदों और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े अन्य आरोपों की भी जांच करती है।

विवाद को लेकर विभिन्न पक्षों का कहना है कि यदि आरोपों में प्रथम दृष्टया तथ्य पाए जाते हैं, तो जांच का दायरा केवल चढ़ावा चोरी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दान राशि के उपयोग, भूमि खरीद की प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर, ट्रस्ट की ओर से पहले भी कई आरोपों का खंडन किया जाता रहा है और कहा गया है कि सभी निर्णय कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप लिए गए हैं।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट में किन बिंदुओं को शामिल करती है, क्या भूमि खरीद से जुड़े आरोपों पर कोई निष्कर्ष देती है, या जांच केवल मूल शिकायत तक सीमित रहती है। मामले का अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।

84 साल के फैशन साम्राज्य का काला चेहरा बेनकाब! 18 वर्षीय युवती के यौन शोषण में दोषी करार डिजाइनर

कनाडा के 84 वर्षीय चर्चित फैशन डिजाइनर पीटर नाइगार्ड को 18 वर्षीय युवती के यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया गया है। अदालत में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

अभियोजन के अनुसार नाइगार्ड ने अपने प्रभाव और रसूख का इस्तेमाल कर पीड़िता को झांसे में लिया और उसका यौन शोषण किया। नाइगार्ड पहले से ही 11 वर्ष की जेल की सजा काट रहे हैं। इस नए मामले में दोषसिद्धि



के बाद उन पर अमेरिका प्रत्यर्पण का खतरा भी मंडरा रहा है, जहां उनके खिलाफ कई अन्य गंभीर यौन अपराधों के मामले लंबित हैं। अदालत इस मामले में 2 अक्टूबर को अंतिम सजा सुनाएगी। यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि प्रभावशाली और धनाढ्य व्यक्तियों के खिलाफ भी यौन अपराधों के मामलों में कानून की कार्रवाई जारी है और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में अदालतें सख्त रुख अपना रही हैं।

हवाई किराए की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त महंगे विमान टिकटों पर नियंत्रण के लिए केंद्र से मांगे नियम, दो सप्ताह में रिपोर्ट तलब



नई दिल्ली। हवाई यात्रा के दौरान टिकटों की अत्यधिक कीमतों और कथित मनमानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि विमान किराया निर्धारण से जुड़े नियमों की एक प्रति दो सप्ताह के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यात्रियों के हितों की रक्षा और विमान किराए में पारदर्शिता

सुनिश्चित करना आवश्यक है। अदालत यह जानना चाहती है कि असामान्य परिस्थितियों या मांग बढ़ने के दौरान किराया तय करने के लिए सरकार के पास क्या नियामक व्यवस्था मौजूद है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि त्योहारों, आपदाओं और विशेष परिस्थितियों के दौरान विमान कंपनियां टिकटों के दाम कई गुना तक बढ़ा देती हैं, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद इस मामले में केंद्र सरकार की नीति और नियामक व्यवस्था पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

दंडवत प्रदर्शन कर अतिथि शिक्षकों ने खोला मोर्चा,

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को अतिथि शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अतिथि शिक्षकों ने लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) का घेराव किया और अनोखे अंदाज में दंडवत होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए डीपीआई आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और भर्ती, री-जॉइनिंग, अनुभव अंक तथा सेवा सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से वे शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन उनके हितों से जुड़े कई मुद्दों का अब तक समाधान नहीं हो सका है। इसी कारण उन्होंने राजधानी में एकत्र होकर अपनी मांगों को सरकार और शिक्षा विभाग के समक्ष मजबूती से रखा। प्रदर्शन के दौरान सबसे प्रमुख मांग री-जॉइनिंग के लिए 90 प्रतिशत उपस्थिति (अटेंडेंस) की अनिवार्यता समाप्त करने की रही। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि कई बार प्रशासनिक कारणों या



अन्य परिस्थितियों की वजह से यह शर्त पूरी करना संभव नहीं हो पाता, जिससे योग्य शिक्षकों को दोबारा कार्य करने का अवसर नहीं मिल पाता। उन्होंने इस नियम में संशोधन कर व्यावहारिक व्यवस्था लागू करने की मांग की। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों ने वर्तमान में होल्ड किए गए सभी अतिथि शिक्षक पदों को तत्काल प्रभाव से खोलने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि जिन पदों पर स्थानांतरण, पदोन्नति या नियमित भर्ती के माध्यम से स्थायी शिक्षक पदस्थ नहीं किए गए हैं, उन रिक्त पदों पर पात्र अतिथि शिक्षकों को कार्य

करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।

ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों ने सेवा अवधि के दौरान मिलने वाली सुविधाओं का भी मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मांग की कि उन्हें नियमानुसार आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश सहित अन्य आवश्यक सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उनका कहना है कि नियमित शिक्षकों की तरह जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। अनुभव अंकों को लेकर भी अतिथि शिक्षकों

ने नाराजगी जताई। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 50 कार्य दिवस पूरे करने वाले अतिथि शिक्षक को 10 अनुभव अंक दिए जाएं। साथ ही वर्ग-1, वर्ग-2 और वर्ग-3 की भर्ती के लिए अधिकतम 100 अनुभव अंक निर्धारित किए जाएं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्तमान स्कोर कार्ड में अनुभव अंकों में की गई कटौती से हजारों अतिथि शिक्षकों को नुकसान हुआ है, इसलिए अनुभव अंकों का पुनः युक्तिसंगत निर्धारण किया जाना चाहिए।

प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों ने कहा कि वे लंबे समय से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें न तो स्थायित्व मिला है और न ही पर्याप्त सेवा सुविधाएं। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। डीपीआई कार्यालय के बाहर हुए इस प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही।

18 बार आवेदन के बाद भी नहीं बनी सड़क

रायसेन। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 18 बार आवेदन देने के बाद भी जब सड़क का निर्माण नहीं हुआ, तो आक्रोशित ग्रामीणों ने 'अब नहीं तो कभी नहीं' का नारा बुलंद करते हुए सांची मार्ग (कलेक्ट्रेट के सामने) पर उग्र प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया।

**दलदल में तब्दील हुई जिंदगी,
स्कूल जाना मुश्किल**

ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में यह मुख्य सड़क पूरी तरह दलदल में तब्दील हो चुकी है। कीचड़ और गड्ढों के कारण ग्रामीणों का पैदल चलना तक दूभर हो गया है, वहीं बच्चों का स्कूल जाना भी लगभग नामुमकिन हो चुका है। कई बार हादसों का शिकार होने के बाद भी जब सुध नहीं ली गई, तो ग्रामीणों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। कलेक्ट्रेट के सामने हुए इस हंगामे के कारण सांची मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। हंगामे और चक्का जाम की खबर मिलते ही कलेक्टर स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने उग्र प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को शांत कराया और सड़क निर्माण का ठोस आश्वासन दिया। कलेक्टर की समझाइश



और जल्द कार्रवाई के वादे के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त किया। लेकिन इस मामले ने सरकारी योजनाएं और उनका क्रियान्वयन धरातल

में कितनी कारगर साबित हो रही है इसकी भी पोल खुल कर सामने आ गई है। हम 18 बार जनता दरबार में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई

नहीं सुनता। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बीमारों को अस्पताल ले जाना आफत है। जब तक ठोस काम शुरू नहीं होता, हमारा आक्रोश थमेगा नहीं।

72 करोड़ के ब्रिज की लागत पहुंची 90 करोड़, 18 महीने में बना सिर्फ ढांचा



भोपाल। निशातपुरा आरओबी ब्रिज का 18 महीने में सिर्फ ढांचा बनकर तैयार हुआ है जिसके चलते लागत करीब 18 करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। आरओबी का निर्माण दिसंबर 2024 में 72 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था जो बढ़कर अब 90 करोड़ रुपए को चुका है। काम समय पर नहीं होने के कारण अब इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। आरओबी ब्रिज का काम जून 2026 में पूरा होना था लेकिन अभी तक सिर्फ भानपुर रोड की तरफ पिलर ही खड़े हुए हैं। कई बार यहां पर अधिकारी दौरा करके जा चुके हैं लेकिन इसके बावजूद काम में तेजी नहीं आई है। ब्रिज के काम देरी होने के चलते आम जनता परेशान है। बड़ी संख्या में लोग मजबूरन में अंडर ब्रिज से होकर गुजरना पड़ रहा है जिसके चलते लंबा जाम भी लग जाता है।

निशातपुरा और करौंद इलाके की करीब 7

लाख की आबादी को 5 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ओवर ब्रिज के काम के चलते सड़क पर जाम लगा रहता है। इसकी चलते से जनता परेशान हो रही है। इलाके की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि संकरा रास्ता होने के कारण यहां से बड़ी एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाती है। किसी मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को करीब 5 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। कोच फैक्ट्री मार्ग पर बने दोनों अंडरपास की चौड़ाई बेहद कम है, इनमें से एक समय में दो ऑटो भी साथ नहीं गुजर सकते, आमने-सामने से वाहन आ जाने पर तुरंत जाम की स्थिति बन जाती है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर यह ब्रिज समय पर बन जाता तो लोगों को काफी फायदा होता। अब रेलवे दावा कर रहा है कि जल्द इसे पूरा किया जाएगा और निर्माण कंपनी से बात की जा रही।

शिप्रा आरती रोकती तो देशभर में होगा आंदोलन: तीर्थ पुरोहितों की दो टूक, पुलिस-निगम कार्रवाई पर फूटा गुस्सा



‘परंपरा से समझौता नहीं’-धार्मिक आयोजन पर रोक के विरोध में संत समाज और पुरोहितों ने दी राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी

उज्जैन। शिप्रा तट पर होने वाली आरती को लेकर विवाद गहरा गया है। पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि शिप्रा आरती पर रोक लगाने या परंपरागत धार्मिक गतिविधियों में बाधा डालने का प्रयास किया गया तो इसका विरोध पूरे देश में किया जाएगा। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि शिप्रा आरती केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उज्जैन की सनातन परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। उनका आरोप है कि प्रशासनिक कार्रवाई से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और वर्षों पुरानी परंपरा प्रभावित हो रही है। पुरोहितों ने प्रशासन से मांग की है कि आरती और धार्मिक आयोजनों पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने से पहले धार्मिक संगठनों, अखाड़ों और तीर्थ पुरोहितों से संवाद किया जाए। उनका कहना है कि आस्था से जुड़े विषयों का समाधान बातचीत से होना चाहिए, टकराव से नहीं। दूसरी ओर प्रशासन का पक्ष है कि यदि किसी स्थान पर कार्रवाई की गई है तो उसका उद्देश्य

कानून-व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना या नियमों का पालन कराना है। प्रशासन ने अभी तक इस पूरे मामले में अपने आधिकारिक पक्ष के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन और तीर्थ पुरोहितों के बीच बातचीत से समाधान निकलता है या विवाद और गहराता है। यदि समझौता नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में यह मुद्दा व्यापक जनआंदोलन का रूप ले सकता है।

मुख्य सवाल

» क्या परंपरा और प्रशासनिक नियमों के बीच संतुलन बन पाएगा?

» क्या प्रशासन और तीर्थ पुरोहितों के बीच वार्ता होगी?

» क्या धार्मिक परंपराओं के संरक्षण के साथ कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा?

» यह विवाद अब केवल उज्जैन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि धार्मिक परंपराओं और प्रशासनिक निर्णयों के संतुलन पर राष्ट्रीय बहस का विषय बनता जा रहा है।

60 हजार करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी, राजनाथ-गडकरी और योगी ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क और आधारभूत ढांचे के विकास को नई गति देने के लिए लगभग 60,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4,850 करोड़ से अधिक लागत की तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

लोकार्पित परियोजनाओं में कानपुर-लखनऊ छह-लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण तथा हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग (पैकेज-4) के चार-लेन निर्माण कार्य शामिल हैं। वहीं शिलान्यास के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर चार-लेन



फ्लाईओवर के निर्माण की आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं से राजधानी लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में यातायात सुगम होगा तथा यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक सड़क नेटवर्क, बेहतर संपर्क और तेज आधारभूत विकास राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार विश्वस्तरीय सड़क अवसंरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

नागपुर दौरे से पहले गरमाई महाराष्ट्र की सियासत
उद्धव ठाकरे पर रवि राणा का तंज 'आरएसएस मुख्यालय जाकर ही होंगे शुद्ध', 'राम रक्षा' आंदोलन पर भी साधा निशाना



मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 18 जुलाई को प्रस्तावित नागपुर दौरे से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है।

विधायक रवि राणा ने उद्धव ठाकरे के प्रस्तावित 'राम रक्षा' आंदोलन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें नागपुर पहुंचने पर पहले डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तभी वे "शुद्ध" हो पाएंगे।

रवि राणा ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता में रहते हुए हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता किया था, इसलिए अब उनके आंदोलन को जनता गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक प्रदर्शन करने से नहीं, बल्कि अपने पुराने विचारों और मूल्यों से जुड़ने से ही विश्वसनीयता लौट सकती है।

उधर, उद्धव ठाकरे 18 जुलाई को नागपुर में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होंगे

जहां राम मंदिर चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरे को लेकर राज्य में राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है और विभिन्न दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

तृणमूल में 'असली पार्टी' को लेकर सियासी संग्राम

बागी गुट के दावे पर ममता खेमे का पलटवार - 'यह मजाक और सर्कस है'



कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में "असली पार्टी" को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बागी गुट द्वारा खुद को "असली तृणमूल कांग्रेस" बताए जाने के दावे को पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने सिरे से खारिज करते हुए इसे "मजाक" और "सर्कस" करार दिया है।

सौगत रॉय ने कहा कि ममता बनर्जी ने स्वयं तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी और अपने नेतृत्व में पार्टी को एक छोटे विपक्षी दल से पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी बनाया। उनके अनुसार,

पार्टी की पहचान और वैधता पर कोई भ्रम नहीं है तथा बागी नेताओं के दावों का कोई राजनीतिक आधार नहीं है।

दूसरी ओर, बागी गुट का दावा है कि वह तृणमूल कांग्रेस की मूल विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है और पार्टी के भविष्य को लेकर नई दिशा देना चाहता है। इस बयानबाजी के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आने वाले चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ते मतभेदों का संकेत माना जा रहा है।



थाना मांधाता पुलिस द्वारा 2023 से फरार 3000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश

जिला खंडवा खंडवा पुलिस द्वारा गंभीर अपराध, महिला सम्बंधित अपराध, अपहरण सम्बंधी अपराध, फरार आरोपी एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही कि जा रही है।

इस क्रम में थाना मांधाता द्वारा फरार आरोपी चंद्रकांत उर्फ गोलू पिता सदन भालेराव निवासी



लौंदी थाना बेड़िया जिला खरगोन को मऊ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। घटना विवरण:- तीन साल पहले सन 2023 में फरियादी ने रिपोर्ट किया था कि आरोपी द्वारा गाली

देकर मारपीट करने कि रिपोर्ट पर थाना मान्धाता में अपराध क्रमांक 400/23 धारा 294, 323, 324 ipc पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया था आरोपी कि गिरफ्तारी सुनिश्चित करने है पुलिस अधीक्षक खंडवा द्वारा 3000 के इनाम उद्घोषणा आदेश जारी किया गया था पुलिस

टीम द्वारा लगातार तलाश करते आरोपी को मऊ जिला इंदौर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।

सराहनीय भूमिका

थाना प्रभारी निरीक्षक अनोखसिंह सिंदया, उनि. लखन डावर, स.उ.नि. आशीष लाड, आर. पंकज की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

शब्दों से परे, अनुभव का विज्ञान- सहजयोग

सहजयोग की संस्थापिका परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी जी का यथार्थ वर्णन शब्दों की सीमा से परे है। विश्व के अनेक देशों के महानगरों से लेकर छोटे-छोटे गाँवों तक लाखों साधकों ने उनके दिव्य आशीर्वाद, गुरुत्व एवं आध्यात्मिक चेतना का अनुभव किया है।

श्री माताजी का अवतरण मानव सभ्यता के विकास की उस महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माना जाता है, जिसने मानव जीवन को उसकी आध्यात्मिक पूर्णता की दिशा प्रदान की। भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता के माध्यम से योग, कर्म और भक्ति का जो दिव्य संदेश दिया था, उसी सनातन ज्ञान को श्री माताजी ने कुंडलिनी जागरण के माध्यम से सहज एवं अनुभवगम्य रूप में प्रत्येक साधक के अंतःकरण में प्रकाशित किया। सहजयोग शब्दों या बौद्धिक तर्क का विषय नहीं, बल्कि आत्मानुभूति का विज्ञान है। शब्द बुद्धि का संवाद है, जबकि परमशक्ति से योग हृदय का समर्पण है, जहाँ शब्दों का कोई स्थान नहीं रहता। श्री माताजी स्वयं परमशक्ति का स्वरूप हैं। उनका वास्तविक स्वरूप किसी भी व्याख्या की सीमा में नहीं बँध सकता। हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते, केवल उनकी असीम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जिस क्षण साधक पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ उनके श्रीचरणों में स्वयं को अर्पित कर देता है, उसी क्षण उनकी कृपा का अमृत जीवन में बरसने लगता है। श्री माताजी प्रेम और करुणा का अथाह सागर, शक्ति का प्रदीप्त सूर्य, शीतल चैतन्य का चंद्र तथा धैर्य की धरा हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है; आवश्यकता केवल अटूट विश्वास, पूर्ण समर्पण और निष्कलंक भक्ति की है। श्री माताजी ने अपने दिव्य संदेश में कहा है— “हर कदम, हर जगह आपके साथ हम खड़े हैं। कहीं भी आप हों, हर स्थान पर हम आपके साथ हैं—काया, मन और वाचा से पूर्णतया। यह हमारा वचन है कि एक पल भी आपसे दूर नहीं। जिस क्षण आप आँखें बंद करके मुझे स्मरण करेंगे, मैं पूर्ण शक्ति के साथ शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ सहित तत्काल आपके पास उपस्थित हो जाऊँगी। एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा, किंतु आवश्यक है कि आप मेरे हों। यदि आप मेरे हैं, तो मैं एक पल में आपके पास आ जाऊँगी। परमात्मा सबको सुखी रखे, सुबुद्धि दे और सन्मति प्रदान करे।” श्री माताजी के इस दिव्य आशीर्वाद एवं सहजयोग के आत्मानुभूति-आधारित मार्ग की जानकारी टोल-फ्री नंबर 1800 2700 800 अथवा www.sahajayoga.org.in के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

माधव नगर कटनी में नकली पान मसाला के कारोबार पर्दाफाश

नवल किशोर

‘लहर’ ब्रांड की डुप्लीकेट पैकिंग करते आरोपी नीलेश पडुजा को माधवनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

कटनी। माधव नगर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला माधवनगर थाना क्षेत्र के बंगला लाइन इलाके से सामने आया है, जहाँ पुलिस ने दबिश देकर नामी गुटखा ब्रांड की डुप्लीकेट पैकिंग करने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली गुटखा और पैकिंग सामग्री जब्त की है।

माधवनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बंगला लाइन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नकली गुटखा तैयार कर उसकी पैकेजिंग की जा रही है। सूचना की तत्पश्चात करते हुए पुलिस टीम ने तत्काल योजना बनाकर बताए गए ठिकाने पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान



पुलिस ने देखा कि वहाँ बाजार में अत्यधिक लोकप्रिय ‘लहर’ गुटखे की हूबहू नकली पैकिंग तैयार की जा रही थी। ब्रांडेड कंपनी के रैपर और पैकिंग का इस्तेमाल कर घटिया दर्जे का तंबाकू और गुटखा बाजार में खपाने की तैयारी थी। पुलिस के अनुसार, इस पूरे अवैध कारोबार का मास्टरमाइंड नीलेश पडुजा नामक व्यक्ति को बताया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मौके से भारी मात्रा में नकली ‘लहर’ गुटखा, खाली पाउच, रैपर्स और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनें व अन्य सामग्री बरामद की गई हैं।

इंदौर धारा मानव रत्न अवॉर्ड-2026 का भव्य आयोजन, विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं का हुआ सम्मान

खुशबू श्रीवास्तव

इंदौर। इंदौर धारा द्वारा आयोजित मानव रत्न अवॉर्ड-2026 का भव्य एवं गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। समारोह में पत्रकारिता, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन इंदौर धारा के प्रधान संपादक रामचंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। यह सम्मान समारोह का 11वां वर्ष रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता



योगेन्द्र महंत ने की। समारोह के सफल आयोजन में अनंत महंत (एडवोकेट), श्रीमती विमला जोशी (सह संपादक), श्रीमती उर्मिला चौधरी, अशोक पाटोदी (जनमत नजर), सुरेश वर्मा बंजारिया, नवीन चौपरी, अखिल

जैन, शिवनारायण कोटिया, निशिकांत अवस्थी, संजय शर्मा (दैनिक क्राइम दर्पण), आनंद श्रीवास्तव, दिनेश शर्मा, पत्रकार विवेक सिंह एवं पत्रकार खुशबू श्रीवास्तव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



टंडन, जिला प्रभारी अनुसूचित जनजाति मोर्चा एकता ठाकुर तथा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन सिंह की उपस्थिति में जिले के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा सभी प्रतिभागियों को डिजिटल शिक्षण का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया

गया। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद सभी के प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र भी डाउनलोड कराए गए और अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर कम से कम 20-20

कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का आह्वान किया गया, ताकि यह अभियान बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। साथ ही उन्हें डिजिटल शिक्षण अभियान से अधिकाधिक लोगों को जोड़ते हुए डिजिटल रूप से सशक्त बनने और देश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक डिजिटल शिक्षण अभियान से जुड़ने तथा इसे जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर मंडी सचिव ओ.पी. खेड़े, बाणगंगा थाना प्रभारी सियाराम सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय गौरक्षा अध्यक्ष भारत संगठन बड़नगर के डॉ. भंवरलाल चौधरी, गौरक्षक शीतल ठाकुर सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रधान संपादक रामचंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान कर उन्हें प्रोत्साहित करना तथा अन्य लोगों को भी समाजहित में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।